

प्रसार भारती
(भारत का लोक सेवा प्रसारक)
प्रादेशिक समाचार एकांश
आकाशवाणी, पटना

प्रसारण:— अपराह्न 02:00 बजे से।

अवधि:— 05 मिनट

राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हरेक वैसे परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिनके परिवार में कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि सरकार बनने के बीस दिनों के अंदर इसके लिए अधिनियम लाया जाएगा। श्री यादव ने कहा कि वे सिर्फ घोषणा ही नहीं करते हैं बल्कि उन घोषणाओं पर अमल भी करते हैं।

विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका है। एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी—रामविलास ने चालीस सीटों की मांग की है। सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर आज पार्टी की एक बैठक भी हुयी। बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बताया कि सीट शेयरिंग और एनडीए में रहने या नहीं रहने का फैसला अंतिम रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान करेंगे। इधर, चिराग पासवान से सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेन्द्र प्रधान और भाजपा के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय दिल्ली में हैं। दूसरी तरफ, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी पन्द्रह सीटों की मांग करके समीकरणों को और उलझा दिया है। सहयोगी दलों की इन मांगों के कारण एनडीए, अभी तक सीट बंटवारे को लेकर किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाया है। इस बीच, जदयू में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, वरिष्ठ नेता ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी और बिजेन्द्र प्रसाद यादव समेत कई नेता मौजूद हैं।

इधर, महागठबंधन के भीतर सीपीआई—एमएल, सीपीआई और मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी ने अपने लिए अधिक सीटों की मांग की है। इससे, गठबंधन के भीतर भी सीट आवंटन को लेकर स्थिति अस्पष्ट है। इस बीच, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने नई दिल्ली में अपनी बैठक में पहले चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया है और उन्हें अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों

में तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। इधर, राष्ट्रीय जनता दल संसदीय समिति की बैठक पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर कल बुलाई गयी है। बैठक में सीट शेयरिंग सहित उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद है।

निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को आगामी बिहार विधानसभा चुनावों और विधानसभा उपचुनावों के दौरान विपक्षी उम्मीदवारों को निशाना बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-एआई के इस्तेमाल पर सख्त निर्देश जारी किये हैं। ये दिशानिर्देश आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत लागू कर दिये गए हैं। आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य प्रकार के विज्ञापनों पर एआई के माध्यम से गलत सूचना फैलाने के लिए सख्ती से मना किया है। इसके अलावा, सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार के लिए साझा की जा रही किसी भी एआई सामग्री को प्रमुखता से चिह्नित करना होगा। निर्वाचन आयोग ने चुनावी माहौल को खराब न करने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी निगरानी का आश्वासन दिया है और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है।

विधानसभा चुनाव के पहले चरण की एक सौ इक्कीस विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना कल जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जायेगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रत्याशी सत्रह अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अठारह अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं, उम्मीदवार बीस अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। पहले चरण का मतदान छह नवम्बर को होगा। दूसरे चरण के तहत एक सौ बाईस विधानसभा क्षेत्रों के लिए अधिसूचना तेरह अक्टूबर को जारी होगी।

इसके साथ ही आकाशवाणी, पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।